

7 राज्यों ने मिलकर बनाई अपराध रोकने की रणनीति

- इंदौर में प. क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक
- अपराध पर रीयल टाइम सूचना साझा करने पर बनी सहमति

नव भारत न्यूज
इंदौर, 7 अगस्त. बदलते अपराध के स्वरूप और अंतरराज्यीय अपराधों से निपटने के लिए सात राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है.

इंदौर में हुई पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक में साइबर अपराध, संगठित अपराध, ड्रग नेटवर्क और आगामी सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा व्यवस्था



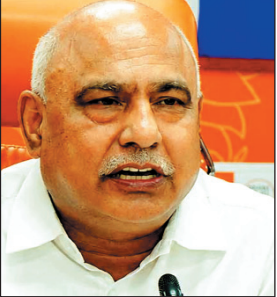
ड्रग नेटवर्क और संगठित अपराध पर संयुक्त अभियान

बैठक में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन और बिक्री से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया कि संबंधित राज्य जल्द संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय अपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए वांछित और इनामी अपराधियों का डाटाबेस साझा किया. भविष्य में संयुक्त अभियान चलाने और अपराधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी .

खादी हमारे स्वाभिमान, स्वदेशी का प्रतीक

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 7 अगस्त. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भोपाल के जवाहर चौक स्थित सरस्वती नगर के खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज एवं वस्त्र खरीदा.

खण्डेलवाल ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम की आत्मा और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को स्वदेशी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया था. आज भी खादी भारतीय



संस्कृति, आत्मनिर्भरता और स्थानीय कारीगरों के सम्मान का प्रतीक बनी हुई है. मध्यप्रदेश के चंदेरी, महेश्वरी, नंदना प्रिंट और बाग प्रिंट जैसी समृद्ध हस्तकला परंपराएं हमारे बुनकर साथियों की अद्भुत प्रतिभा, परिश्रम और सांस्कृतिक विरासत को पहचान हैं. कृषि के बाद हैंडलूम एवं बुनकर उद्योग देश में रोजगार का सबसे बड़ा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 7 अगस्त भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणादायी तिथि है. वर्ष 1905 में इसी दिन कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद हुआ था. उसी ऐतिहासिक विरासत को स्मरण करते हुए देशभर में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है . देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45 लाख बुनकर हैंडलूम उद्योग में जुड़े हुए हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं .

आधार है. हमारे पारंपरिक वस्त्र न केवल भारतीय संस्कृति और विरासत के संवाहक हैं, बल्कि लाखों परिवारों का आजीविका का भी प्रमुख साधन हैं.

लहार अनुभाग में बिजली के खंभों से तार चोरी का नहीं थम रहा सिलसिला

बांके तिलुनायक
लहार 7 अगस्त. लहार अनुभाग में बिजली के खंभों से तार चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

गिरवास-बरहा मार्ग पर पांच खंभों से तार गायब, तीन खंभे क्षतिग्रस्त चोरी या कोई और खेल, जांच के घेरे में मामला



ताजा मामला असवार थाना क्षेत्र के गिरवास और बरहा गांव के बीच का है, जहां अज्ञात बदमाश करीब पांच बिजली के खंभों से विद्युत तार उतारकर ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर

इतनी लंबी दूरी तक तार उतारना सामान्य चोरी जैसा नहीं लगता, बल्कि यह पूरी योजना के तहत किया गया काम प्रतीत होता है।

चोरी या कुछ और
घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मामला सिर्फ चोरी का है या इसके पीछे कोई और कहानी है, यह जांच का विषय है। यदि चोरी हुई है तो इतने भारी मात्रा में

तार आखिर कहां खपाए जा रहे हैं और कबाली नेटवर्क तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है?

ग्रामीणों में रोष- ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली लाइन की नियमित निगरानी और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी छिंदी-सुंदरपुरा मार्ग पर बिजली के खंभों से तार चोरी की घटना सामने आ चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चोर इतने लंबे समय तक बिजली के तार काटकर ले जाते हैं और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगती?

हीरक जयंती पर सुप्रीम परिवार का मेगा वृक्षारोपण अभियान

नवभारत न्यूज
मालनपुर 7 अगस्त. सुप्रीम कंपनी अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर 'डायमंड जुबली सेलिब्रेशन - 60 Years of Excellence एवं एजीक्यूटिव डायरेक्टर एस जे तपारिया' के 81वें जन्मदिन के अंतर्गत मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली इस वर्ष भी 501 पौधे आरोपित किए गए साथ ही आगामी समय में 7000 पौधे ग्रीन बेल्ट में आरोपित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके पूर्व 1100 पौधे पिछले साल लगाए गए थे जो की 95ज ग्रोथ रेट के साथ जिंदा है और सभी लाइव है।



इस विशेष अवसर पर नगर परिषद मालनपुर सीएमओ रेहमान अली जैदी, डीजीएम विद्युत विभाग हरीश मेहता, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राधेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण शर्मा, अविनाश शर्मा नेशनल अध्यक्ष QCFL, राजेश खन्ना यूनिट हेड SRF,

मुकुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं सुप्रीम परिवार के बरिष्ठ अधिकारी यूनिट हेड संतोष काबरा, मनीष पांडे ,अभिषेक दाधीच, सीरभ गुप्ता, कार्मिक प्रबंधक योगेश चौहान, बुजभान सिंह, मुकेश मेवाफरोश के साथ सभी कर्मचारियों ने उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया.

लहार में शासकीय शिक्षकों की निजी कोचिंग पर सवाल

नवभारत न्यूज
लहार 7 अगस्त. नगर लहार में शासकीय शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो

सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक वर्षों से चला रहे निजी कोचिंग सेंटर,जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

रहे हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का दावा है कि पुरानी गल्ला मंडी क्षेत्र में कई ऐसे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिनका संचालन शासकीय शिक्षक स्वयं कर रहे हैं। आरोप है कि यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही है, लेकिन शिक्षा

विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे।

सूत्रों के अनुसार कुछ शासकीय शिक्षक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को निजी कोचिंग में पढ़ने की सलाह देते हैं। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
नगर में चर्चा है कि संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बावजूद इन कोचिंग संस्थानों का संचालन वर्षों से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शासकीय शिक्षक निजी कोचिंग चला रहे हैं तो विभागीय नियमों के तहत इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार को पहुंचाई जा रही आर्थिक क्षति

जबलपुर. जुर्माना राशि नहीं वसूल कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मिश्र ने याचिका का निराकरण करते हुए जिला कलेक्टर को जुर्माना राशि वसूलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं। टीकमगढ़ निवासी अजय प्रताप सिंह की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि माइनिंग अधिकारी के द्वारा अनावेदक राजा राम राय पर दो लाख 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

दबंग दुनिया पर 48 करोड़ की कर देनदारी

फर्जी सर्कुलेशन और विज्ञापनों से आय दिखाने का आरोप, 75 हजार का जुर्माना

नव भारत न्यूज
इंदौर, 7 अगस्त. दबंग दुनिया पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (डीडीपीएल) के खिलाफ सेंट्रल जीएसटी विभाग ने करीब 48 करोड़ रुपए की कर देनदारी तय की है. विभाग के संयुक्त आयुक्त योगेश पांडुरंग ने जारी आदेश में कंपनी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

कार्रवाई में अखबार के प्रसार और विज्ञापन से जुड़ी आय को लेकर अनियमितता का उल्लेख किया है. विभाग की जांच में दावा किया है कि दबंग दुनिया पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अखबार के प्रसार की

संख्या वास्तविक आंकड़ों से अधिक दर्शाई गई. इसके आधार पर 5.73 करोड़ रुपए की आय बताई गई. वहीं, कथित फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से 5.93 करोड़ रुपए की आय दर्शाने का भी उल्लेख किया है. इन दोनों मदों में

बताई गई 11.66 करोड़ रुपए की आय को आधार बनाकर विभाग ने कर देनदारी निर्धारित की. विभाग ने 3.68 करोड़ रुपए जीएसटी, 65 लाख रुपए सेस और 44.50 करोड़ रुपए सेस 2 सहित करीब 48 करोड़ रुपए की मांग तय की है.

जांच में डीडीपीएल और ईटीसीएल (ऐलोरा टोबैको) के बीच कारोबारी संबंध होने का भी उल्लेख किया है. विभाग का दावा है कि दोनों संस्थाओं के बीच जुड़ाव था और डीडीपीएल के माध्यम से ऐलोरा टोबैको से जुड़ी कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही थीं . आदेश में अखबार के कुछ कर्मचारियों और रिपोर्टरों के नाम पर कथित फर्म संचालित होने का भी जिक्र है. इसमें एक क्राइम रिपोर्टर के नाम पर फर्म, एक कर्मचारी को दूसरी कंपनी में निदेशक बनाए जाने और एक अन्य कर्मचारी के माध्यम से कथित फजी पते पर कंपनी पंजीकृत कराने की बात कही गई है. विभाग ने कर सलाहकार के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को भी संस्थान से जुड़ा कर्मचारी बताया है.

गलत जानकारी देने पर एसडीओ ने कोर्ट में मांगी माफी

हाईकोर्ट ने सरकार के साथ नगर निगम को भी इलाज खर्च उठाने के दिए निर्देश

नव भारत न्यूज
इंदौर, 7 अगस्त. अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में इलाज खर्च को लेकर पेश किए गए शपथ पत्र में हुई गलती को लेकर एसडीओ ने हाईकोर्ट में माफी मांगी. कोर्ट को बताया कि जिन भुगतानों को पूरा बताया गया था, वे अभी प्रक्रिया में हैं. हाईकोर्ट ने घायलों के इलाज खर्च की जिम्मेदारी सरकार के साथ नगर निगम को भी उठाने के निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के आदेश के पालन में जूनी इंदौर के एसडीओ घनश्याम धनगर

कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में गलती से यह उल्लेख हो गया था कि अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल के बकाया भुगतान किए जा चुके हैं, जबकि वास्तव में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि संबंधित राशि एक सप्ताह में जमा कर दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हादसे में घायल लल्लू पटेल, विजय पटेल, सुभाष सिंह ठाकुर और गोपाल मलान्कर के बॉम्बे अस्पताल और अरबिंदो अस्पताल में हुए इलाज खर्च की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. संबंधित अस्पतालों के माध्यम से एक सप्ताह में भुगतान की

कार्रवाई पूरी करने की बात कही गई. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में अंतरिम मुआवजे के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. वहीं, इंदौर नगर निगम की ओर से बताया कि बॉम्बे अस्पताल प्रबंधन को घायलों की निशुल्क

ड्रेसिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा है.

इनका कहना
कोर्ट ने गलत जानकारी वाले शपथ पत्र पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे . हमने कोर्ट को बताया है कि भुगतान प्रक्रिया में है और जल्द पूरी कर दी जाएगी.

घनश्याम धनगर, एसडीओ, जूनी इंदौर

इलाज खर्च में देरी पर कोर्ट ने जताई चिंता ...
हाईकोर्ट ने पाया कि घायलों को भुगतान में देरी हो रही है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया में लगाने वाले समय के कारण घायलों को परेशानी नहीं होनी चाहिए . इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए कि इलाज और मुआवजे से जुड़े खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ इंदौर नगर निगम भी उठाएगा . सुनवाई के दौरान अवंतिका गैस लिमिटेड को भी पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं . कोर्ट ने तीन कार्य दिवस में नोटिस जारी करने और एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है .

पात्र हितग्राही जनलाभ योजना से वंचित नहीं रहेगा

नवभारत न्यूज
जबेरा/दमोह, 7 अगस्त.. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश में संचालित जन विश्वास अभियान 'के माध्यम से शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर



सिंह परमार ने मंगल भवन, जबेरा में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियानके तहत आयोजित गरिमायम जनसंवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए. संस्कृति

राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा जबेरा विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ हुआ.

जनहितैषी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के प्रथम शिविर में 160 आवेदनों का हुआ निराकरण एक ही स्थान पर आमजन को मिलेंगे कई लाभ : शुक्ल

भोपाल, 7 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार रीवा जिले में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आरंभ हो गया है. सिरमौर विकासखण्ड में आयोजित अभियान के प्रथम शिविर में आम जनता से मिले 322 आवेदन पत्रों में से 160 का मौके पर निराकरण किया गया.

शिविर में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और उनको कठिनाईयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान सरकार की



सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिविर में आम जनता को एक ही स्थान पर कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. जिन कार्यों के लिए आम जनता को कार्यालयों में भटकना पड़ता है उनका लाभ शिविर में किया जा रहा है. आम जनता की कठिनाईयाँ दूर करना सुशासन की पहल है. शिविर में उप मुख्यमंत्री

ने कहा कि जन विश्वास अभियान में अधिकारी आम जनता से संवाद करने के साथ-साथ स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवाद कर रहे हैं. अभियान के दौरान शासन की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग होगी.

शिविर में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शिविर के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान से प्रशासनिक गतिशीलता और मानीटरिंग बढ़ेगी. यह अभियान सुशासन को बढ़ावा देने में सफल होगा. जनसंवाद से आम जनता की कठिनाईयों को दूर किया जा रहा है. आर्थिक विकास के लिए उद्यमियों के साथ उद्यम संवाद भी किया जा रहा है. जिला और विकासखण्ड स्तर के सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं की शिविर के माध्यम से मानीटरिंग कर रहे हैं.

सहकारी समितियों से किसानों को जोड़ेंगे : महेन्द्र

- बैटन से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान
- अपेक्स बैंक के अध्यक्ष ने किया शिरकत

सिंगरौली, 7 अगस्त. मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खम्हरिया में आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपेक्स बैंक भोपाल के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने अभियान के महत्व की जानकारी ग्रामीणों को दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह अभिनव पहल दूरस्थ अंचलों में निवासरत नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है. अब प्रत्येक



शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शासन के 36 विभागों के अधिकारी पहुंचकर आमजन की समस्याओं का मौके पर निराकरण करेंगे. इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्र नहीं लगाने प ?गे. उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान निश्चित रूप से आमजन के जीवन में खुशहाली लाने में सफल होगा. इसके पश्चात महेंद्र सिंह यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

सिंगरौली शाखा में आयोजित सदस्यता अभियान एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा बैठक में भाग लिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. विधायक रामनिवास शाह, ननि अध्यक्ष देवेश पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह, रमपति जायसवाल, सीमा जायसवाल, जिप सीईओ जगदीश गोमे सहित अन्य मौजूद रहे.